कुछ अलग | पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत चलाई जाएंगी बसें, नगर विकास विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा, उच्च स्तर से मंजूरी के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा

सुविधा: लखनऊ समेत 19 शहरों में ई-बसें चलाने की तैयारी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए प्रदेश के 17 नगर निगमों समेत 19 शहरों में ई-बसें चलाने जा रही हैं। यह बसें पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत चलाई जाएंगी।

नगर विकास विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है और जल्द ही उच्च स्तर से मंजूरी के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बड़े शहरों में 150-150, मध्य शहरों में 100-100 और छोटे शहरों में 50-50 बसें चलाए जाने की योजना है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

740 बसें मौजूदा समय में चल रही हैं प्रदेश में

50 -50 बसें छोटे शहरों में चलाने की तैयारी है

150 के करीब ई बसें लखनऊ में चलेंगी

17 नगर निगमों में बसें चलाने की योजना है

- फेम इंडिया योजना के तहत प्रदेश के 14 शहरों में मौजूदा समय 740 छोटी एसी ई-बसें चलाई जा रही हैं
- फेस-दो में 300 बसें और ली जानी थीं, पीएम ई-बस सेवा के शुभारंभ के बाद खरीद पर मंथन

लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद में चलेंगी सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसें

शासन स्तर पर तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के मुताबिक, बड़े शहरों खासकर लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में 150-150 और नई बसें चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। आगरा, झांसी, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद व गौतमबुद्धनगर में 100-100 बसें चलाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा, रामपुर व सहारनपुर में 50-50 बसें चलाने की योजना है।

केंद्र सरकार की फेम इंडिया योजना के तहत प्रदेश के 14 शहरों में मौजूदा समय 740 छोटी एसी ई-बसें चलाई जा रही हैं। फेस-दो में करीब 300 बसें और ली जानी थीं, लेकिन सरकार ने पीएम ई-बस सेवा का शुभारंभ कर दिया है। इसके चलते फेम इंडिया फेस-दो में अब नई बसें नहीं खरीदने पर मंथन चल रहा है। नगर विकास विभाग अब पीएम ई-बस सेवा में नई बसों की मांग करेगा। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए उच्च स्तर पर पहले चरण की बातचीत हो चुकी है। इसके आधार पर प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

एक से दो साल में सभी बसें उपलब्ध करा दी जाएंगी

नगर विकास विभाग इन बसों की चरणवार मांग करेगा, जिससे केंद्र से बसें मिलती रहें। हर चरण में इन शहरों को 10 से 15 बसें दी जाएंगी और एक से दो साल के अंदर सभी बसें इन शहरों को उपलब्ध करा दी जाएंगी। इन बसों के रख-रखाव और चार्जिंग के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे खराब होने की स्थिति में ठीक किया जा सके व जरूरत के आधार पर चार्जिंग होती रहे।